MRA AN USIUM The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 170] No. 170] नई दिल्ली, मंगलबार, अप्रैल 17, 2012/चैत्र 28, 1934 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2012/CHAITRA 28, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 296(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कोर्ट मास्टर (समूह "ख") भर्ती नियम,2012 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2 **लागू होना:** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।
- 3.पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान-पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 4. अर्ती की पदित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पदिति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरहता: वह व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1			
(8)	सीपे अती के तिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दक्षा में लागू होंगी	लागू महीं होता	- "
(7)	सीधे अती किए जाने वाले व्यक्तियाँ के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं होता	
(9)	सीधे मतीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	लागु नहीं होता	
(2)	चयन अध्या अच्यन पद	लागू नहीं होता	
(4)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतन बैंड 2 ,9300- 34800 स्पये(ग्रेड वेतन 4200 स्पये)	
(3)	वर्गीकरण	साधारण सिवित सेवा,समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	
(2)	मद संख्या	1* (एक) *(2012) कार्यभार के आधार पर पर परिवर्तन किया जा सकता है।	,
(£)	पद का नाम	कोर्ट मास्टर	•

	ř
≥	The state of
<u>2</u>	
<u>₽</u>	5
ر ا ا	The state of the s
ž	<u></u>

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री
- (ii) किसी सरकारी कार्यालय/विभाग/न्यायिक प्राधिकरण में न्यायालय की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने का दस वर्ष का अनुभव ।
- (।ii) कम्प्यूटर का कार्यसाधक जान ।

टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी आशिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले(उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान साहित एक श्रेणी में विलय हो गया है अरितनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर परिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा जिसके अंतर्गत

अल्पकालिक	अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की आतेम ताराख का 56 वर्ष स		
अधिक नहीं होगी	होगी।		
े डिक्का	टिप्पण :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अईक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के		
नियं भिसी	लिए किसी अधिकारी दवारा 1-1-2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय		
वितम आयो	वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया		
	गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर	-	
आधारित त	आधारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		3

[फा. स. ए-12018/9/2010-एस ओ (ई एस सैल)] बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 17th April, 2012

GS.R. 296(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Court Master in the Adjudicating Authority, under Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

- 1. Short Title and commencement. (1) These rules may be called the Adjudicating Authority Court Master (Group 'B') Recruitment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of post, classification and Scale of Pay. The number of post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** The method of recruitment to the said post, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 5. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

135261/12-3.

Provided that the Central Government may, if satisfied that, such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether, selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Court Master	1* (One) *(2012) Subject to variation dependent on workload	General Civil Services, Group 'B', non-Gazetted, ministerial	Pay Band-2 Rs.9300 - 34800 (Grade Pay Rs.4200)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether bv direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

By deputation

Deputation:

Officers under the Central/State Government/Union Territories:

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-1 Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre/department; or
 - (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-1 Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre/ department; and
- (b) possessing the following educational qualification:
 - (i) Bachelor's degree from a recognised university or Institute.
 - (ii) Two years' experience in maintenance of record of court proceedings in a government office/ department/judicial authority.
 - (iii) Working knowledge of computers.

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend

only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.

Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Committee exists, what is its	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
composition (12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-12018/9/2010-SO (ES Cell)] BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.